विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश

"ईज ऑफ डूइंग बिजनस में 2016-17 में यूपी 14वें स्थान पर था। अब दूसरे नंबर पर आ गया है। 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट यूपी में स्थापित हुई और चीन से निवेश आया। ये यूपी के लिए उपलब्धि है।"
योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

लखनऊ | सोमवार, 11 अक्तूबर 2021
अमर उजाला
amarujala.com

पारदर्शी व्यवस्था से योगी सरकार बनी निवेश मित्र

यूपी तरक्की की राह पर सरपट दौड़ रहा है। इसकी गवाही डीपीआईआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की रैंकिंग दे रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार से पहले यूपी पूरे देश में 14वें नंबर पर था। सुधारों की छलांग से रैंकिंग में यूपी दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यानी, लेबर रेगुलेशन से लेकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन तक किए गए रिफॉर्म का असर साफ दिख रहा है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत भूखंड आवंटन के लिए पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में संशोधन के अनुसार अब वाणिज्यिक भूमि का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, औद्योगिक भूमि का आवंटन, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से तथा आवासीय भूखंडों का आवंटन, लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के माध्यम से निजी औद्योगिक पार्कों/आस्थानों में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान किया है। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बुंदेलखंड व पूर्वांचल में न्यूनतम 20 एकड़ तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में न्यूनतम 30 एकड़ की पात्रता सीमा निर्धारित की गई है।

लैंड बैंक सृजन को लेकर किए सुधार

निवेश को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में नीतिगत निर्णयों से लैंड बैंक में वृद्धि के लिए अनेक सुधार किए गए। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के लिए जोनल विनियमों में संशोधन के जरिए मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति प्रदान की गई।

ग्रेटर नोएडा में स्टाफ हाउसिंग के लिए 50 एकड़ या उससे अधिक के औद्योगिक भूखंडों में 15 प्रतिशत एफएआर की अनुमति दी गई।

पांच वर्षों के भीतर भूमि का उपयोग करने में विफल रहने पर आवंटित भूमि को निरस्त करने के लिए उप्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया। इससे ग्रेटर नोएडा में लगभग 17 एकड़ क्षेत्रफल वाले 50 भूखंडों का आवंटन निरस्त करके पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध कराया गया।

औद्योगिक भूमि के लिए एफएआर को बढ़ाकर 3.5 कर दिया गया (2.5 अनुमन्य +1 क्रय योग्य एफएआर) तथा उद्योगों को उनकी सरप्लस भूमि को सब-डिवाइड करने की अनुमति प्रदान की गई।

भूमि को गैर-कृषि घोषित करने के लिए 45 दिनों के भीतर आवेदन का निस्तारण करने का आदेश जारी किया गया और औद्योगिक भूमि के लिए लैंड पूलिंग नीति अधिसूचित की गई।

निवेश के लिए 3,200 एकड़ अतिरिक्त जमीन तैयार

सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 3,200 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की है।

- मौजूदा वित्त वर्ष में उप्र. औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने 1214.73, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) 400, वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेटर नोएडा) 1752.56, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) 1,071.77 और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने 300 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित की।
- विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा विगत साढ़े चार वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 3,908 भूखंडों में लगभग 3,324.22 एकड़ भूमि का अनेक परियोजनाओं को आवंटन किया गया है। इनमें लगभग 61,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।

भूमि आवंटन की प्रगति
मार्च 2017 से मार्च 2021 तक

प्राधिकरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)	निवेश (करोड़ रुपये में)	संभावित रोजगार
यूपीसीडा	784.63	6,539	66149
नोएडा	584.96	13,960	1,39,000
ग्रेटर नोएडा	841.33	25,340	64,000
यीडा	1,073.85	14,725	2,47,413
गीडा	39.45	766.98	4,964

फास्ट-ट्रैक मोड पर भूमि आवंटन

सीलिंग सीमा से अधिक कृषि भूमि की खरीद में आसानी के लिए राजस्व संहिता में संशोधन किया गया। इसके अनुमोदन का अधिकार जिला-स्तर के अधिकारियों को प्रदान कर दिया गया। साथ ही सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा एवं इससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन की तिथि से 15 दिनों के अंदर फास्ट-ट्रैक मोड पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। इस वरीयता आवंटन प्रणाली के माध्यम से पांच कंपनियों को भूखंड आवंटित भी किए जा चुके हैं।

- इनमें ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर के लिए हीरानंदानी ग्रुप के ₹55,000 करोड़ के निवेश और नोएडा में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इकाई के लिए ₹5.22 करोड़ का मेक इंडिया के प्रस्तावित निवेश की परियोजना भी शामिल है। मेक इंडिया के प्रोजेक्ट से 2500 लोगों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है।

निर्यात केंद्रों की रेल कनेक्टिविटी का ध्यान

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) का ग्रेटर नोएडा में दादरी में जंक्शन है, जिससे प्रदेश को अद्वितीय लॉजिस्टिक्स लाभ प्राप्त है। ये कॉरिडोर प्रमुख निर्यात केंद्रों, जैसे गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर, इटावा, कन्नौज, दीन दयाल नगर, प्रयागराज आदि के लिए अंतिम मील की रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।

मौजूदा समय में ईडीएफसी के लिए 46.17 हेक्टेयर भूमि की संशोधित मांग में से 41.91 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है तथा डब्ल्यूडीएफसी के लिए कुल 41.0614 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। हाल ही में ईडीएफसी पर भाऊपुर (कानपुर)-खुर्जा (अलीगढ़) पथ का शुभारम्भ किया गया।

इन परियोजनाओं के विकास के परिणामस्वरूप राज्य में विभिन्न औद्योगिक केंद्रों की क्षमता में वृद्धि होगी तथा नई औद्योगिक परियोजनाएं भी स्थापित होंगी। इसमें ग्रेटर नोएडा में दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के आच्छादित क्षेत्र के किनारे 747.5 एकड़ की एकीकृत टाउनशिप का विकास सम्मिलित है। भौतिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित कर लिया गया है तथा इंफॉर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) और ई-गवर्नेंस अवस्थापना का विकास किया जा रहा है, जबकि 154 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की गई है।

इसी तरह राज्य सरकार ने अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत "एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर" (आईएमसी) के विकास के लिए प्रयागराज में 1,141 एकड़ और आगरा में 1,064 एकड़ भूमि चिन्हित की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

ग्रेटर नोएडा में ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इकाई के लिए 264.71 करोड़ रुपये के निवेश से 2500 रोजगार सृजित होंगे। इसी तरह यूरलेक्स के यीडा क्षेत्र में पैकेजिंग इकाई की 255 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव से 300 लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा।

शालविस स्पेशियलिटीज की हमीरपुर में पेस्टिसाइड्स/फंगीसाइड्स उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इससे 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन सभी को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।

विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे भी बढ़ाएंगे उद्योगों की रफ्तार

विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे के माध्यम से अंतिम व प्रथम मील कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। इससे सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ कृषि, वाणिज्य, पर्यटन एवं उद्योगों की आय में वृद्धि होगी। ये परियोजनाएं एक्सप्रेस-वे द्वारा आच्छादित क्षेत्रों में स्थित विभिन्न उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों व कृषि उत्पादन क्षेत्रों को लखनऊ और दिल्ली से जोड़ने के लिए एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में सहायक होंगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

340.8 किमी लंबा : गाजीपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अमेठी आदि को लखनऊ से जोड़ता है

- परियोजना की अनुमानित लागत 23,349.37 करोड़ रुपये। परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है।
- सुल्तानपुर जनपद में एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई-पट्टी विकसित की जा रही है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे

296.07 किमी लंबा : 4 लेन का प्रवेश-नियंत्रित बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे प्रमुख निर्यात केंद्रों जैसे- चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन औरैया एवं इटावा को बुंदेलखण्ड क्षेत्र से त्वरित कनेक्टिविटी हेतु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जोड़ता है।

- परियोजना की कुल लागत 14,849.09 करोड़ रुपये है तथा परियोजना लगभग 71.36 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे

91.352 किमी लंबा : 4-लेन का प्रवेश-नियंत्रित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे गोरखपुर के आसपास के प्रमुख निर्यात केंद्रों को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से तथा राज्य लिंक की राजधानी से जोड़ता है।

- परियोजना की कुल लागत 5,876.68 करोड़ रुपये है तथा परियोजना लगभग 27.94% पूर्ण हो चुकी है।

गंगा एक्सप्रेस-वे

इस 594 किमी लंबे प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे की परियोजना लागत लगभग 36,229.67 करोड़ रुपये है।

यह एक्सप्रेस-वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज में तथा आसपास के प्रमुख निर्यात केंद्रों को जोड़ेगा।

- लगभग 93 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है तथा बिडिंग प्रक्रियाधीन है।
- शाहजहांपुर में एक्सप्रेस-वे पर भी वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई-पट्टी भी प्रस्तावित है।

मीडिया सॉल्यूशन इनीशिएटिव